

288

न्यायालय श्री मानू रायस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

श्री श्री 23/9/16 /निग./ /2015-16,

निग 3288-J/16

द्वारा आज दि. 23/9/16 को

1. रामचरन तनय स्व. रामलाल अहिरवार

2. प्रियाम पुत्री स्व. रामलाल अहिरवार

3. नरवादिद्या पुत्री स्व. रामलाल अहिरवार तहस्त

निवासी ग्राम महेबा तह. व जिला- उत्तरपुर म. प्र. । -----आवेदकगण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन ।

-----अनावेदक

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म. प्र. मू. रा. संहिता 1959 के तहत ।

निगरानी विरुद्ध निर्णय योग्य अधीनस्थ न्या. श्री मानू नायबतहसीलदार मण्डल महेबा तह 0 उत्तरपुर के रा. प्र. क्र. 8/अ63/2012-13, में पारित आ. दि. 8-8-2016, से दुधी होकर।

महोदय,

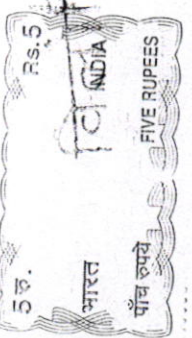
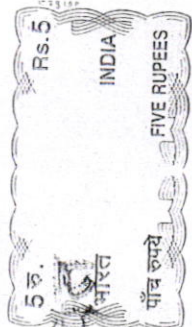
आवेदकगण श्री मानू के समक्ष सादर निम्न लिखित तथ्यों एवं आक्षेपों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं:-

1:- यह कि उक्त निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगणों द्वारा मौजा महेबा तह. उत्तरपुर की भूमि ख. नं. 2644, 2646, 2647/1, एकत्र रकबा 1.845 है. भूमि आवेदकगणों के स्व. पिता रामलाल तनय कन्हैया अहिरवार को उक्त भूमि सन् 1971-72, में उक्त भूमि का पट्टा भूमि स्वाधी स्व. व पर प्राप्त हुआ जो बिना किसी सहम आधिकारी के आदेश के गैरहकदार स्वैच्छासकीय पट्टेदार तत्कालीनपट्टवारी द्वारा लेव कर दिया गया था जो नामांतरण पत्र क्र. 22 में पा. आ. दि. 11-9-85, को अधीनस्थ न्यायालय श्री मानू तहसीलदार महोदय द्वारा सामूहिक रूप से अन्य कास्त कारोंके साथ भूमि स्वाधी घोषित किया गया जिसका अमल उसरा वर्ष 1987-88 में दर्ज हो चुका था । तथा शासन द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख आदेश प्र. 537/11/मू. प्र. /मू. स. /2008, में आ. दि. 1-2-2008 में आदेश पारित किया गया था कि 1 जनवरी 1999 के बाद प्रदत्त किये

1/2/1

57
23/9/16
R/S
23/9/16

23/9/16



R/S

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3288 -एक/2016

जिला-छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
27-9-2016	<p>यह निगरानी नायब तहसीलदार मण्डल महेबा तहसील-छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/अ-6अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2016 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है.</p> <p>2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम महेबा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2644, 2646, 2647/1 कुल रकबा 1.845 हेक्टेयर को ग्राम पटवारी द्वारा विक्रय से प्रतिबन्धित की टीप अंकित कर दी. जिसे सुधारें जाने हेतु संहिता की धारा -115-116 एवं 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया - जिसे तहसीदार द्वारा निरस्त कर दिया गया -उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है.</p> <p>3. आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित आधारों पर जोर देते हुए बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि का पट्टा आवेदक के पिता को भूमिस्वामी स्वत्व पर सन 1971-72 में हुआ था. जिसे तत्कालीन पटवारी द्वारा लेख कर दिया था. जो नामान्तरण पंजी क्रमांक-22 पर आदेश दिनांक 11-9-1985 को भूमिस्वामी घोषित कर दिया गया. जिसका अमल राजस्व अभिलेखों में सन 1987-88 में किया जा चुका है. पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश के एवं आवेदकगण को सूचना, एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना</p>	अ

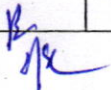





किसी अधिकार के राजस्व अभिलेखों में विक्रय से प्रतिबन्धित अंकित कर दिया गया. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है. अतः निगरानी स्वीकार किये जाने तथा उपरोक्त प्रविष्टि को विलोपित करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की.

4. अनावेदक- शासन के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही होना बताते हुए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया.

5. उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन एवं अवलोकन किया. अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि आवेदक के पिता स्व. रामलाल को शासकीय भूमि पर पट्टा प्रदान किया गया था. तथा तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 11-09-1985 को पट्टेदार को भूमिस्वामी घोषित किया गया था. जिसका अमल राजस्व अभिलेखों में किया जाना प्रमाणित है. प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने प्रकट होता है कि आयुक्त भू-अभिलेख के आ0दि01-2-2008 जिसके द्वारा ऐसे पट्टे जो 1 जनवरी 1999 के बाद प्रदत्त किये गये हैं उन्हें राजस्व अभिलेखों में विक्रय से प्रतिबन्धित अंकित किया जाये. उक्त आदेश से ही प्रमाणित होता है कि उक्त आदेश मात्र उन्हीं पट्टों पर ही प्रभावशील है जो 1998 के बाद प्रदत्त हो. पट्टवारी द्वारा 1971-72 में प्रदत्त पट्टे की भूमि जिस पर 1985 में भूमिस्वामी अधिकार उदभूत हो चुके हैं. उसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विक्रय से प्रतिबन्धित अंकित किया जाना प्रमाणित है. तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किये बिना तथा बिना प्रकरण की परिस्थितियों को देखे आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है. जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है. पट्टवारी द्वारा की गयी अवैध प्रविष्टि को मनमाने आधारों पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है. तहसीलदार द्वारा जो आधार



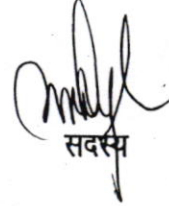


निग0 प्रकरण क्रमांक 3288-एक /2016 जिला- छतरपुर

आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त करने हेतु दिये है वे विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार मण्डल महेबा द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ-6अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2016 निरस्त किया जाता है तथा पटवारी द्वारा की गयी विक्रय से प्रतिबन्धित प्रविष्टि को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है. आवेदकगण को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के कारण उसे भूमि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है. उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है. अभिलेख भेजा जाये. प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

R/12


सदस्य